

सिंगापुर में मिले एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 60 हजार करोड़ के एमओयू : योगी मुख्यमंत्री ने दो दिनों में 100 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से की भेंट



सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी व अन्य • सूचना विभाग

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिंगापुर में टीम यूपी को लगभग एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 60 हजार करोड़ रुपये के एमओयू 'इन्वेस्ट यूपी' द्वारा संपन्न किए जा चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह निवेश प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो दिनों में उन्होंने 100 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से भेंट की है। सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, गृहमंत्री और ऊर्जा मंत्री के साथ भी उनकी सकारात्मक व सार्थक वार्ता हुई। इसके अतिरिक्त प्रमुख फिनटेक कंपनियों के अध्यक्ष व सीईओ के साथ भी बैठकें की गईं। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे में भी सिंगापुर की कुछ कंपनियों ने निवेश किया है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो

सीएम ने उग्र इन्वेस्टमेंट रोड शो में निवेशकों को किया संबोधित

मुख्यमंत्री बिजनेस फेडरेशन सिंगापुर द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में बिजनेस लीडर्स संवाद कार्यक्रम में निवेशकों को संबोधित किया। उन्होंने संवाद में शामिल सभी निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी निवेश सिंगापुर की कंपनियों द्वारा किया जाता है।

उन्होंने टेमासेक, जीएसएस ग्रीन, यूएससी, जीआइसी, सैप कोर्स, ब्लैक स्टोन के अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की। इससे पहले एआइ सैट्स के साथ हुए एमओयू (समझौता ज्ञापन) के अनुसार एआइ सैट्स नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

परिसर में एक अत्याधुनिक कार्गो कैंपस का निर्माण करेगी। यह कार्गो कैंपस न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एयर फ्रेट और लाजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस परियोजना से निर्यात-आयात गतिविधियों को गति मिलेगी, विशेषकर इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा, कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा। एससीई के साथ हुए एमओयू के अनुसार दोनों पक्ष संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए दौरे व लीडरशिप डेलिगेशन का आयोजन करेंगे। दो माह के भीतर विस्तृत परियोजना समझौतों पर बातचीत और छह माह के भीतर उन्हें अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा।

सुविधा और एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहालिंग) विकसित करने के लिए सिंगापुर की दक्षता का अध्ययन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में

भारत सहित विश्व के अनेक विमान अपने एमआरओ कार्यों के लिए सिंगापुर आते हैं। यह सुविधा भारत में, विशेषकर जेवर में विकसित की जा सकती है।